



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 395]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण****अधिसूचना**

मुंबई, 24 नवम्बर, 2015

**सं.टीएएमपी/13/2009-वीपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता, एतद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण****मामला सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी****विशाखापत्तनम पत्तन न्यास**

.....

**आवेदक****आदेश**

(नवम्बर 2015 के 17 वें दिन पारित)

यह आदेश विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंधित है।

2. वीपीटी के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/13/2009 दिनांक 18 फरवरी 2011 के अंतर्गत अनुमोदित किये गये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में 31 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित की गई थी। इस प्राधिकरण द्वारा वर्तमान दरमानों की वैधता की तिथि दो बार बढ़ायी गई है और पिछली बढ़ोत्तरी दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के आदेशानुसार 30 सितंबर, 2015 तक थी।

3.1 वीपीटी के दिनांक 08 फरवरी, 2013 के पत्र के साथ 22 मार्च, 2013 के पत्र अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर, 2005 के प्रशुल्क दिशा निर्देशों के अंतर्गत संबंधित उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार विमर्श किया गया।

4.1. इस दौरान मोत परिवहन मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अंतर्गत नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' जारी कर दी गई जिसे इस प्राधिकरण द्वारा भारत के

राजपत्र सं 30 पर दिनांक 27 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया। यह नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी हो गई है।

4.2. पोत परिवहन मंत्रालय की नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' में उल्लिखित प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रशुल्क निर्धारण पद्धति से बहुत भिन्न है अतः वीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस परिप्रेक्ष्य में इस प्राधिकरण द्वारा जारी 13 फरवरी, 2015 के आदेश के अंतर्गत वीपीटी के दरमानों के सामान्य परिशोधन के प्रस्ताव को बंद कर दिया गया था। वीपीटी को पोत परिवहन मंत्रालय की घोषित नई प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत नया परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दे दिया गया है।

5. प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 1.5 के अनुसार इस संप्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क नीति 2015 के कार्यान्वयन के लिए महापत्तन न्यासों के परामर्श से भारत के राजपत्र में, 04 जून 2015 को राजपत्र सं 207 के अंतर्गत कार्यकारी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वीपीटी द्वारा नई प्रशुल्क नीति-2015 के अनुसरण में अपना प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है। वीपीटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति-2015' के अनुसरण में ही कार्रवाई की जाएगी।

6.1. क्योंकि वीपीटी के मौजूदा दरमानों विस्तारित वैधता 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो जानी थी इसलिए वीपीटी द्वारा उनके 28 सितंबर, 2015 के पत्र द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखे पूरे कर लिए गए हैं तथा लेखा परीक्षण की रिपोर्ट के लिए दे दिए गए हैं। क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, नई प्रशुल्क नीति-2015 के अनुसार दरमानों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने में कुछ समय लग सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में वीपीटी द्वारा परिशोधित दरमान प्रस्ताव पेश करने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक या दरमान के निर्धारित किये जाने की तिथि तक जो भी पहले हो का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

6.2. वीपीटी के अनुरोध के मद्देनज़र, यह प्राधिकरण द्वारा वीपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता की अंतिम तिथि 31 मार्च 2016 या संशोधित दरमानों के कार्यान्वित होने की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, को बढ़ायी जाती है। जहां तक खंड 6 के क्रम सं.2 पर उल्लिखित खुले स्थान के लिए मौजूदा दरमानों में लाइसेंस (भंडारण) फीस का संबंध है, इस प्रशुल्क मद की वैधता, वीपीटी द्वारा प्रस्तुत पृथक प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण के अनुमोदनाधीन संशोधित लाइसेंस फीस पृथक आदेश के द्वारा प्रभावी होने तक बढ़ायी जाती है।

6.3. वीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर यह प्राधिकरण, वीपीटी का 31 दिसंबर, 2015 तक अपने दरमानों में संशोधन से संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव पेश करने का समय प्रदान करता है। वीपीटी को परामर्श दिया जाता है कि वह हर हालत में विस्तारित समय के अंदर अपना प्रस्ताव अवश्य पेश कर दे।

6.4. 01 अप्रैल, 2013 के बाद वीपीटी के किसी अन्य मामले का निस्तारण नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति-2015' के अनुसार किया जाएगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/143/15(283)]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November, 2015

**No. TAMP/13/2009-VPT.**—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/13/2009-VPT

The Visakhapatnam Port Trust

-----

Applicant

### ORDER

(Passed on this 17th day of November, 2015)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009-VPT dated 18 February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 31 March, 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of existing SOR of VPT on couple of occasions; the last extension being till 30 September, 2015 vide Order dated 28 April, 2015.

3.1. The proposal filed by the VPT vide its letters dated 8 February 2013 along with its letter dated 22 March, 2013 under the tariff guidelines of 2005 was taken on consultation with the concerned users/user associations.

4.1. In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January, 2015 issued the new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015” which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January, 2015 by this Authority. The new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015” has come into effect from 13 January, 2015.

4.2. The tariff fixation process envisaged in the new Tariff Policy of 2015 for Major Port Trust by MOS, is significantly different from the tariff fixation method stipulated in the Tariff Guidelines of 2005. Hence, the proposal filed by VPT could not be processed under 2005 guidelines. In view of this, this Authority vide its Order dated 13 February, 2015 had closed the VPT proposal for general revision of its Scale of Rates. The VPT has been advised to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015 announced by the MOS.

5. As per Clause 1.5 of Tariff Policy, 2015, this Authority has notified the working guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015 in consultation with all Major Port Trusts in the Gazette of India on 4 June, 2015 vide Gazette No.207. Further, the VPT is yet to file its proposal following new Tariff Policy, 2015. The proposal when received from the VPT will have to be processed following the new Tariff Policy, 2015.

6.1. Since, the extended validity of the existing SOR of VPT, was to expire on 30 September, 2015, the VPT vide its letter dated 28 September, 2015 has stated that preparation of final accounts for 2014-15 was completed and submitted to Audit for its Report. As the audit report for the year 2014-15 is yet to be received from C&AG, preparation of the SOR proposal in accordance with new Tariff Policy, 2015 may take some more time. In view of this, the VPT has requested to grant time upto 31 December, 2015 to file the SOR revision proposal or till the date of finalisation of SOR, whichever is earlier.

6.2. In view of the request made by the VPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of VPT from the date of its expiry till 31 March, 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier. As regards License (Storage) fee for open space prescribed at Sl. No. 2, under section 6 – charges for License (Storage) fee in the existing Scale of Rates, this Authority extends the validity of this tariff item till revised license fee being approved by this Authority in a separate Order based on the separate proposal of VPT comes into effect.

6.3. In view of the submission made by the VPT, this Authority grants time till 31 December, 2015 to VPT to file its proposal for revision of its SOR. The VPT is advised to file its proposal within the extended time limit without fail.

6.4. The treatment of additional surplus, if any, accruing to the VPT for the period beyond 1 April, 2013 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Extty./143/15(283)]